# पाँचवाँ जल सम्मेलन

# जल बिरादरी


राष्ट्रीय जल बिरादरी

34/46, किरण पथ, मानसरोवर

जयपुर-302020

फोन फैक्स : 0141-2393178, 2231092, 01465-2225043

Email: jalbiradari@rediffmail.com

## पाँचवाँ राष्ट्रीय जल सम्मेलन
## जल बिरादरी

आजकल रोज हो रहे नये-नये सम्मेलनों में जल विशेषज्ञ, राजनेता, सरकारी अधिकारी भाग लेते रहते हैं। लेकिन इन सम्मेलनों में जमीन से जुड़े हुए लोगों की आवाज इन एअर कन्डीशनर कमरों तक पहुँचने के अलावा 'इस शताब्दी का लक्ष्य', 'सबके लिए पानी' जैसे बड़े शब्द सुनने को मिलते हैं। गांव में किये गये छोटे-छाटे जल संरक्षण के कार्य कुछ समय बाद बड़ा योगदान देते हैं। आजकल नदी-जोड़ पर बहुत चर्चा हो रही है।

क्षेत्र के अनुसार प्राकृतिक तथा भूसांस्कृतिक बदलते हुए घटकों को सोचे बिना हम अनेक समस्याओं के समाधान के लिए एक ही हल ढूँढ़ना चाहते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे सामने होने के बावजूद भी हम अन्य जगह पर ढूँढ़ने में लगे हुए हैं। हमारा अहंकार, इस निर्णय प्रक्रिया में मिट्टी से जुड़े हुए, विशेषज्ञ लोगों से, किसानों से हमें दूर रखता है।

पिछले 20 सालों से तरुण भारत संघ विकेन्द्रित जल प्रबन्धन लेकर स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहा है। जल प्रबन्धन का यह आन्दोलन पूरे देश में फैल गया है। इस आन्दोलन में पूरे देश से लोग आकर जुड़ने लगे हैं। इस भाईचारे के आन्दोलन को जल बिरादरी के नाम से जाना जाता है।

जल बिरादरी जल, जंगल और जमीन पर काम करने वाली संस्थाओं तथा लोगों की बिरादरी है, जो लागों को पानी के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करके, उनका पानी पर हक कायम करने के लिए कार्य करती है । 1998 से जल बिरादरी राष्ट्रीय व प्रादेशिक जल नीति को जनोन्मुखी बनाने हेतु सम्मेलन, चर्चा जल यात्रा द्वारा लोगों को जाग्रत करने का प्रयास कर रही है।

जल बिरादरी की शुरुआत तरुण भारत संघ द्वारा अप्रैल 2001 में नीमी गांव में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 7000

जल योद्धाओं ने भाग लिया था और यहीं से लोगों के पानी के हक का जन आन्दोलन शुरू हुआ था । इस आन्दोलन की जिम्मेदारी तरुण भारत संघ के श्री राजेन्द्र सिंह को सौंपी गयी।

जल बिरादरी समाज के उस हिस्से का समूह है, जो मानता है कि पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जिसमें आम व्यक्ति, संस्थाएं, संगठन, आन्दोलनकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पैरवीकार, लेखक, कलाकार, जनप्रतिनिधि, राजनेता, मजदूर, किसान और व्यापारी हर कोई शामिल है। जल बिरादरी लोगों में जाग्रति लाने के साथ ही राष्ट्रीय व प्रादेशिक जल नीति को जनोन्मुखी बनाने हेतु प्रयास कर रही है।

## जल बिरादरी द्वारा पूर्व में आयोजित जल सम्मेलन :

### पहला जल सम्मेलन

20 से 22 अप्रैल, 2001 गांव नीमी में हुआ,

- जिसमें जल बिरादरी की स्थापना हुई।

### दूसरा जल सम्मेलन

5 और 6 मार्च, 2002 को दिल्ली में

- राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में किया गया।

### तीसरा जल सम्मेलन

1 और 2 अप्रैल, 2003 को सेवाग्राम में आयोजित हुआ।

- इस सम्मेलन में जल साक्षरता आन्दोलन, राष्ट्रीय जल नीति का विरोध व अस्वीकार किया गया और, नई जल नीति के बारे में जागरूकता आदि मुद्दों पर चर्चा हुई।

### चौथा जल सम्मेलन

25 और 26 जून, 2004 को नई दिल्ली में किया गया।

- सम्मेलन में नई सरकार को जल निजीकरण, नदी जोड़ को लेकर घोषणा-पत्र दिया गया।

## पाँचवाँ जल सम्मेलन

9 से 12 नवम्बर, 2005 को तरुण भारत संघ के तरुण आश्रम, भीकमपुरा में आयोजित किया गया है। उसमें निम्न विषयों पर चर्चा होगी -

- वैश्वीकरण, जल निजीकरण, जल संरक्षण और प्रबन्धन के संदर्भ में भारत की भूमिका।
- नई पर्यावरण नीति तथा नदीजोड़ परियोजना पर चर्चा।

सदियों से हम ये मानते थे कि जल, जंगल, जमीन और वन्यजीव तथा पर्यावरण हमारे साझा संसाधन हैं। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी लोगों की थी। इस मान्यता को विकास की विभिन्न क्रान्तियाँ जैसे कि औद्योगीकरण तथा हरित क्रान्ति ने पिछले दो सौ सालों में तोड़ा है। फलस्वरूप, आज प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की वजह से हमारा भूजल भण्डार खत्म होने के कगार पर है।

विकास के नाम पर हम धीरे-धीरे प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाने वाले जल संरक्षण के परम्परागत ज्ञान को भूलते जा रहे हैं । लेकिन इक्कीसवीं सदी में इस परम्परागत ज्ञान को आगे लाने की जरूरत है और इसलिए दुनिया के जल विशेषज्ञ भी जमीन के नीचे छुपे हुए इस ज्ञान को फिर से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

### परम्परागत जल संरक्षण

भारत में पहले, समाज द्वारा अपने संसाधनों का संवर्द्धन और प्रबन्धन खुद किया जाता था । गांव के लोग पानी संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण करके स्वयं उसका प्रबन्धन भी करते थे। इस प्रक्रिया में समाज का हर घटक शामिल होता था। यह विकेन्द्रित जल प्रबन्धन का खरा उदाहरण था। धीरे-धीरे जल प्रबन्धन की जिम्मेदारी बदल गयी और राजतंत्र के हाथ में जाने से विकेन्द्रित जल प्रबन्धन से केन्द्रीय जल प्रबन्धन में बदल गया। अतः हम अपने परम्परागत जल प्रबन्धन के ज्ञान को भूल गये और सरकार पर निर्भर हो गये।

आज पानी की कमी एक विकराल समस्या है, जिसका सरकार के पास कोई हल नहीं है। लेकिन राजस्थान के गांव के लोगों ने गांव में जोहड़ बनाकर अपने परम्परागत ज्ञान को पुनर्जीवित करके इस समस्या का समाधान किया है। इन गांवों

की हरियाली को देखकर इन गांवों की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन साझा प्रयासों को देख कर लगता है कि लोग प्रकृति से जितना लेते हैं, उतना प्रकृति को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये साझे प्रयास संगठन-शक्ति के प्रतीक हैं।

## विकेन्द्रित जल प्रबंधन

हमें भांवता-कोल्याला के समाज द्वारा किये गये पानी के काम से सीख लेनी चाहिए। यहाँ सालाना मात्र 50 सेमी वर्षा होती है । 1987 में यहां पानी की समस्या थी। कुएं सूख गये थे, खेत खाली थे। बेकार, लाचारी और बीमारी से दुखी होकर लोग पलायन कर रहे थे। स्कूल और स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। तरुण भारत संघ के प्रोत्साहन से उन्होंने अपने गांव में काफी जोहड़ बनाये। इस कार्य में लोगों ने श्रमदान करके सहयोग किया। गांव में ग्रामसभा बनायी जो कि हर महीने बैठक करके अपने प्राकृतिक संसाधन, जल और जंगल का संरक्षण करते हैं। जोहड़ बनाने से उनके कुओं में पानी हो गया और गांव में खुशहाली आयी। अरवरी नदी पुनर्जीवित हुई। इन कार्यों से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब उन्हें पानी के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़ता तथा वे अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने लगे हैं ।

जल बिरादरी और तरुण भारत संघ यह मानता है कि विकेन्द्रित जल प्रबन्धन देश की पानी की समस्या का समाधान है। यह बात कार्यकर्ताओं द्वारा की गयी पदयात्रा, चर्चाओं, जल यात्राओं आदि प्रयासों में झलकती है। हमें लगता सरकार, समाज द्वारा किये कार्यों में सहयोग करेगी। इसमें गांव के लोगों ने जोहड़ बनाये जो ना सिर्फ भूजल स्तर में सुधार के लिए थे, बल्कि आसपास के जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए भी थे। इन छोटे-छोटे प्रयासों का समाज तथा प्रकृति पर सकारात्मक प्रभाव होता है जबकि बड़े प्रयास अधिकतर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं ।

## जल निजीकरण

1 अप्रैल, 2002 की राष्ट्रीय जल नीति पानी को सम्पत्ति मानती है और जल के निजीकरण को प्रोत्साहित कर रही है । यह नीति जल को निजीकरण की तरफ ले जा रही है, जो लोगों की जल संरक्षण में बची-कुची भागीदारी को भी खत्म करेगी। इसलिए इस जल नीति पर विचार होना जरूरी है ।

जल और नदियों का निजीकरण रोकने की जरूरत है। जल का निजीकरण गुलामी का रास्ता है। इसे रोकने हेतु समाज को तुरन्त खड़ा होना चाहिए।

सरकार द्वारा किया गया केन्द्रीय जल प्रबन्धन गांव तथा शहरों में जल सुविधा देने में असमर्थ रहा है। कुछ लोग इस समस्या का समाधान जल प्रबन्धन के निजीकरण के रूप में देखते हैं।

जल प्रबन्धन अगर विकेन्द्रित हो तो लोग प्राकृतिक संसाधनों को बचाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे, जिससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जा रहा अतिदोहन अपने आप ही रुक जायेगा। इस जल नीति में सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। कौन जानता है कि एक दिन गंगा किसी की निजी सम्पत्ति होगी। पहले तो यह असम्भव लग रहा था लेकिन अभी पानी दूध से भी महंगा है। जब पानी बाजारू वस्तु बनेगा तब वह बाजारू शक्तियों के हाथ में होगा।

जल बिरादरी यह मानती है कि पानी किसी की निजी सम्पत्ति न होकर साझा प्राकृतिक संसाधन है। यह बिकाऊ वस्तु नहीं है। यह समाज का मुख्य अंग तथा साझा भविष्य है। इसलिए जल स्रोतों के संरक्षण में समाज की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए जल बिरादरी सरकार से कहती है कि पानी को 'वस्तु' न कहकर राष्ट्र का 'साझा प्राकृतिक संसाधन' घोषित करे तथा पानी का निजीकरण न करके समाज द्वारा किये गये पानी के कार्यों को बढ़ावा दे। इससे जल प्रबन्धन में जन जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

**प्रदूषण**

*जल का स्वास्थ्य समाज के स्वास्थ्य में झलकता है।*

जल बिरादरी ने यह महसूस किया कि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो प्रदूषण बढ़ता रहेगा। और पानी की बीमारियों से बच्चे और बड़े मरते रहेंगे। भूजल के गिरते स्तर के कारण पानी की गुणवत्ता गिर जायेगी।... इसके लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान की जरूरत है। जल बिरादरी को लगता है कि जब तक नई जल नीति में जल व पर्यावरण के नये मापदंड नहीं जुड़ेंगे,

तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। जल बिरादरी का उद्देश्य है नीति बनाने वाले, योजनाकारों को जागरूक करके उनके सामने आने वाली समस्याओं को सकारात्मक लेकर हल करना । जल बिरादरी चेतना जगाकर रचनात्मक जल सत्याग्रह करने वाली है।

अगर यह स्थिति लोगों को जीवनयापन के लिए भूजल का शोषण करने पर मजबूर करती है तथा पर्यावरण हितैषी नहीं है तो हमें नये दस्तूर व कानून बनाने की जरूरत है।

प्रदूषण की बात करते ही हमारा ध्यान शहरी इलाकों की तरफ जाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और औद्योगीकरण शहरी विकास की निशानी है। इस विकास ने ही हमारी नदियों को गन्दे नाले में बदला है। शहर की इन समस्याओं मुख्यतः नदी को प्रदूषित करने वाले गन्दे पानी की निकासी और पुनः शुद्धि द्वारा समाधान करने के लिए तुरन्त प्रयास करने की जरूरत है।

23 दिसम्बर, 2002 में जल बिरादरी ने श्री राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय जलयात्रा लगभग देश के 29 राज्यों में गई । इस जलयात्रा के दौरान स्थानीय जल समस्याओं को समझने की कोशिश की गई, तो पता चला कि भारत की अधिकतर नदियाँ मर रही हैं या प्रदूषित हो चुकी हैं या फिर बड़े बान्धों में या नहर में कैद हो गई हैं।

## नई पर्यावरण नीति

21 अगस्त, 2004 में पर्यावरण मंत्रालय ने नई पर्यावरण नीति का प्रारूप जारी किया। जल बिरादरी का सोचना है कि इस प्रारूप का मूल उद्देश्य निजी (विदेशी) निवेश को आमंत्रित करना है ना कि पर्यावरण बचाना है।

पर्यावरण तथा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीति बनाना एक अलग बात है तथा विदेशी निवेश को आमंत्रित करने वाली नीति बनाना दूसरी बात है। देश के आर्थिक विकास के लिए दूसरी बात ज्यादा फायदेमंद है पर इसके अपने नुकसान हैं। इस नीति का प्रारूप पर्यावरण की समस्याओं की जड़ को

समझकर बनाना चाहिए। तभी हम जीवन के खतरे और जल प्रदूषण से बच सकते हैं।

हमें देश के जलाशयों का दोहन तथा प्रदूषित करने से पहले उन्हें ठीक करना होगा। अगर हम छोटे फायदों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। पहले से ही काफी जंगल काटे जा चुके हैं, जिससे प्राकृतिक-चक्र को नुकसान हुआ है। क्या हम अपनी जैव-विविधता को खोने का खतरा मोल लेंगे?

भविष्य की जलनीति और योजना धरती पर पानी के महत्व को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। पानी सीमित घटक है जो कि मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है।

हमारी पर्यावरण नीति की नींव भारतीय आस्था ही होनी चाहिए। इसके आधार पर हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और यह आस्था हमारे रीति-रिवाज, विचारधारा, परम्परागत जीवन पद्धति में झलकती है। भारतीय सभ्यता हमेशा से ही प्रकृति को सर्वोपरि मानती रही है।

## नदीजोड़

*जब भी हमने प्रकृति के चक्र में तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो हमें उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं। इन बुरे परिणामों से बचने के रास्ते हमें प्रकृति ही दिखा सकती है। प्रकृति हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षक है। जब हम प्रकृति के विपरीत कुछ भी करते हैं, तो हमारे जीवन का संकट बढ़ जाता है।*

जल बिरादरी नदीजोड़ से ज्यादा लोगों को नदी से जोड़ना तथा जल, जंगल के संरक्षण तथा प्रबन्धन में लोगों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी समझती हैं।

2002 में नदीजोड़ योजना को शुरू करने हेतु टास्क फोर्स बना था। इस परियोजना के दो हिस्से हैं। हिमालय की 14 नदियों को जोड़ने की योजना जिसका खर्च 375000 करोड़ और दक्षिण की 16 नदियों को जोड़ने की योजना जिसका खर्च 185000 करोड़ रुपये का है । देश की 30 नदियों को जोड़ने की यह योजना सरकार

द्वारा बाढ़-सुखाड़ की समस्या से मुक्ति तथा देश में खेती तथा औद्योगिक विकास करने वाली योजना के रूप में प्रस्तुत की ।

जल बिरादरी यह मानती है कि नदियों को जोड़ने से पहले हमें उन्हें पुनर्जीवित करना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि नदी-जोड़ की बजाय नदियों की समस्याओं पर ध्यान दें जिससे नदियों को बचाया जा सके।

*भारत में नदीजोड़ परियोजना के दुष्प्रभावों को समझना कठिन कार्य है । हमारे देश के भविष्य को बदलने की क्षमता रखने वाली है। यह परियोजना सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के साथ भी खिलवाड़ होगी। यह परियोजना हमारे भूगोल के साथ-साथ हमारे पर्यावरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसका पूर्व-आंकलन करना भी एक असाध्य लक्ष्य है। अंत में, नदी-जोड़ परियोजना के विभिन्न आशयों पर जन स्वीकृति बनाए बिना हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते।*

जल बिरादरी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, भूसांस्कृतिक, नदीघाटी तथा क्षेत्रीय स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। यह सहज, स्वस्फूर्त, मजबूत, सक्रिय जल आन्दोलन है । जल ही जीवन है। जैसा जल होगा वैसा ही मन और शरीर बनेगा। जल पर छाये संकट हमारे जीवन का संकट है। इस संकट से बचने हेतु जल चेतना पैदा करके जल रचनाओं को संरक्षित करने में आ रही सरकारी बाधाओं को हटाने हेतु सत्याग्रह करने वाली जल बिरादरी का ही नाम जल आन्दोलन है।

जल बिरादरी हमेशा से ही इस बात पर जोर देती रही है कि हमें पानी और जंगल दोनों बचाने चाहिए। पेड़ पानी का पिता है और धरती पानी की माँ है। हमारे पूर्वज इस चक्र को समझते थे । वे कहते हैं 'हम जितना प्रकृति से लेते हैं, उतना ही प्रकृति को वापस लौटायें ।

जल बिरादरी इस प्रक्रिया में सबको शामिल करती है। सरकार और निर्णयकर्ता इस बात को समझें। नदी-जोड़ भ्रष्टाचार जोड़ है। जल शोषण, प्रदूषण, जल विवाद, जल दोहन की समस्याओं का समाधान प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कर सकते हैं।

परम्परा का अर्थ होता है, ऐसा सुन्दर काम जो किसी समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़े। हमारी जल संग्रह की परम्परा उस कसौटी पर खरी उतरी है। आज जब आधुनिकतम जल प्रबन्धन समाज की प्यास न बुझा पाया, उसे बाढ़-अकाल से न बचा पाया, तब हम पाते हैं कि राजस्थान के समाज द्वारा किये गये जांचे-परखे काम हमें सीख दे सकते हैं। हिमाचल में दूधातोली लोक विकास संस्थान, उफरैखाल जैसे काम हमें तारने के लिए आये हैं। परम्परागत जल प्रबन्धन की यह जल बिरादरी पूरे देश में एक समय बहुत मजबूत थी। फिर से समाज उस दिशा में जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही उसका जल संकट कम होगा।

**हम जितना जल प्रबन्धन की परम्परा को पुनर्जीवित करेंगे उतनी ही पानी की समस्या कम कर सकते हैं।**

# 5th Water Convention

# Jal Biradari

**Rashtriya Jal Biradari**
34/46. Kiran Path, Mansarovar
Jaipur-302020
Telefax:0141-2393178, 2231092, 01465-2225043
Email: jalbiradari@rediffmail.com

## 5th National Water Convention

## Jal Biradari

Many conferences take place around water with experts, politicians, Government. representatives, scientist etc. But most often the voices of the common people are not being heard-they on the ground who are actually making a difference on a small scale basis. Instead we hear big words like "Millennium Development Goals"; "Water For All"; "Foreseeable Future" "Sustainable Development" the list is getting bigger with every new conference.

In the meantime small silent actions and efforts which with time have made a major contribution in conserving water, are being done at community level.

Nowdays there is a huge talk regarding interlinking of rivers?

How can we implement such a mega project to achieve solutions to all the existing problems at a large scale when we know about the differences regarding physical and cultural aspects which varies within a mile?

We look at the Moon for Lakhs and Lakhs of alternatives when answers lie in front of us.

Our Arrogance has kept the very people away from the decision making process, whose expertise is like a second nature to them, whose heart and mind remain close to the soil and its pattern from dawn to dusk.

All round the country grassroots movements are taking place such as Tarun Bharat Sangh who are working on decentralize water management and doing policy and advocacy in association with the village community for last 20 years.

As the grassroot movement actions is echoing across the country more and more people are getting involved in water conservation and more recently advocating on policy level issues on water giving initiative to Jal Biradari.

This movement was initiated in April 2001 in the working field area of TBS at Nimbi village (near Jaipur). Around five thousand water warriors from all over the country participated in the convention and from here the issue of people's water right and country wide water movement started. The responsibility of leading the movement was given to Shri Rajendra Singh a senior volunteer of Tarun Bharat Sangh.

Jal Biradari is a brotherhood of individuals from all walks of life, farmers groups, social groups, voluntary organizations, Non government organization, research institutions, social scientist, water experts basically all who are concerned about the conservation of water, forest and soil and promote water conservation work as well as re-establish the community rights over water.

Since 1998, Jal Biradari through its awareness programs, conferences, jal sammelans and discussions is aiming to develop people-oriented National and State Water Policy.

Jal Biradari in itself is a culture, brotherhood associated with the nature. This is an organization of individuals who believes to rejuvenate the nature by living with the nature. It's a villager's organisation.

## Jal Biradari: earlier conventions

### The 1st Water convention

20th - 22nd April 2001 in Nimmi Village

- Formation of a National Jal Biradari

### 2nd Water convention

5th - 6th March 2002 in Delhi

- Opposition of National water policy

### 3rd Water convention

1st - 2nd April 2003 in Sewagram Aasharm, Wardha

- Water Literacy movement, rejection of the new water policy and creating awareness about the new water policy among common people through Jal Yatra's.

### 4th Water convention

25th – 26th June 2004 in New Delhi

- Drafting memorandum for the new Government on privatization of water, linking of river basin.

### 5th Water convention

9th - 12th November 2005 at Bhikampura village.

- India's Future of Water Governance and Envision of the Leaks of Globalization and Privatization in Water Management
- To review the initiative taken by the new Govt. at centre on the issue of River linking and Environment policy.

For centuries, the line of thinking that soil, water, forest, wildlife and the whole environment are the common resource of the local people bestowed by the almighty to be managed as a "trustee" was the commonly accepted worldview. This age-old balance has been disturbed at an accelerating pace in the last two hundred years, and every revolution and counter-revolution has indeed increased the depth of the fall: the Industrial revolution, the "Green" revolution and many others.

We have now come to a time where our natural resources are feeling the extreme exhaustion from our relentless extraction of ground water and it is slowly reaching a point of no return. In the name of "progress" we have slowly stepped away and buried those ancient knowledge of conserving water which had worked in harmony with nature for hundreds of years. Ironically in the 21st century this ancient knowledge is once again being brought back to the surface as even the "water experts" of this world are now digging holes in the earth to try and find the very roots that they had once buried: Indigenous Wisdom in Water Conservation.

## Indigenous Tradtional Water Conservation

Not long ago communities themselves were fully involved in the conservation and management of water. They undertook construction of water harvesting structures with the help of kings and businessmen and other well to do persons of the area and themselves took the initiative for their maintenance and management. In this way everybody was participating in the process of water conservation and it was the best example of decentralized water management system. Gradually with the change in governance and political systems there was a shift from decentralized to centralized water management system which resulted in the loss of indigenous knowledge and system resulting in complete dependence on the Government even for providing water.

Nowadays water scarcity is a rampant problem and the Government seems to be empty of solutions, but in whole of Rajasthan the local communities, villages have revived traditional knowledge of rain water harvesting and decentralized water management system by fixing old structures or building new ones. If you happen to take a stroll in the area you will hear the rhythm of "pump" near by and will see the lush green fields and healthy forests. As a result of these collective community efforts, people start thinking of themselves in terms of doers and not recipients. Being alone makes one helpless while in togetherness lie the seeds of strength.

**Decentralize Water Management**

A perfect example of this resurgence of water conservation and decentralized local water management system can be found in the River Arvari basin in the village of Bhanwta- Kolyala which is located in the northern part of Rajasthan and gets an annual rainfall of 50 cm. In 1987 this village was suffering from acute water scarcity, their wells were dry, their fields were parched, education and health facilities were non existent. With the motivation and facilitation from TBS they started constructing a number of johads "water structures". Some villagers contributed by hard cash and others by labour. They also created a village council" Gram Sabha" that meets once a month to discuss the management of their natural resources, water and forest conservation. Over the years the construction of rainwater harvesting structures not only filled their wells, improved the water supply, rejuvenated the Arvari River but also dramatically affected the life style of the women in villages. They no longer had to walk miles to fetch water and could for the first time see their daughters being educated.

Jal Biradari hand in hand with TBS strongly feels that decentralized community based water management system is a solution for our country and their yatras, campaigns, and discussions are a reflection

of this. We hope that the Government will rise to the occasion and give full support to the community practices of water conservation. In which not only the villagers build structures to recharge their ground water but they also build similar structures for rejuvenating the neighbouring forests. These small local interventions slowly and slowly have a very positive impact both on nature and communities while too often giant steps are destructive to nature and people.

**Water Privatization**

The National Water Policy declared on 1st April 2002 defined water as an asset-tradable commodity and is promoting water privatization. This drive for privatization and commodification will further destroy community responsibility in water conservation and its sustainable use.

The centralized system of water management adopted by the State failed to deliver water services to both rural and urban populations. The solution to this problem is advocated by many as privatization of water resource management.

It is necessary to stop the privatization of water and river. The privatization of water leads to new doors of slavery and the whole society needs to come forward soon to fight the crisis.

If the management of water resources is decentralized and handed over to the local community, they realize their moral responsibility to conserve the natural resources. Once this is achieved the commercial exploitation of ground water resource by multi-national companies will be naturally brought to a halt. The Government is only paving way for privatization of water. Who would have known that one day we would talk of "The Ganges" as a private property? For several years it seemed improbable but today we pay more for water than milk.

Jal Biradari believes that water is a common natural resource rather than an asset of an individual. It is the basis of life and common future of the country. So community has equal rights in conservation of water resources.

A request is there from Jal Biradari to the Government of India to declare water as a National common resource rather than an asset and to promote community based efforts of water conservation instead of giving water control to the private sector.
Then only a truly participatory form of water management system can be established for sustainable solutions.

**Pollution**

*The health of our water is a reflection of the health of our society.*

Jal Biradari has come to realize that if we just sit gazing at clouds, pollution will continue to rise and waterborne disease will keep on taking the life of children and adults every second. One of the consequences of fast depletion of ground water is the deterioration of the quality of water. So, unless we bring awareness on National, State, Regional and Local level, unless we recharge our ground water aquifer and harvest rain water we will soon be suffering for water.

Jal Biradari feels that unless the New Water policy frame takes cognition of changing water and Environmental parameters, it will be too late to tackle the problems. Jal Biradari's concern is to sensitize the planners, policy makers and technocrats to wake up and face the emerging challenge in a positive way.

If the circumstances force people to over extract ground water for their livelihood and are not environment friendly then there is a need for new laws to be incorporated.

When one talks about pollution one's attention will be directed towards the urban area. Air pollution, Water pollution, Industrial pollution are the symbols of Urban Development. There is an urgent call for solving these environment problems through better management of urban affairs particularly Waste Water disposal which is threatening the health of our rivers.

In December 2002 Jal Baridari organized a two years Jal yatra lead by Mr Rajendra Singh, covering more than 20 states all over the country. In this attempt they tried to comprehend the regional and local issues of water across India and learnt that most of the rivers in India are either dying, highly polluted or are diverted through dams and canals.

**New Environment Policy**

On August 21st 2004 the Ministry of Env. and Forests released a new Env. Policy. Jal Biradari is under the impression that the central theme of the Draft Policy is not environment protection. It is an attempt to smear over cardinal principles of environmental conservation to attract private (especially foreign) investment. It is one thing to draft a policy in accordance to the immediate calls of the people, and environment. It is another path to draft a policy that aims in giving more flexibility to industries and foreign companies. Even though the 2nd choice might seem appealing at first sight for the economical growth of this country there is a definite backlash to this choice. The draft policy first and foremost needs to look at the roots of environment destruction.

The bodies of water of this country needs to be healed before giving more room for extractions and pollution. If one looks only at short returns then we will enter a very bleak future. Already too many forests have being taken down which is destructive to the natural cycle. Are we taking a chance of losing our biodiversity? Water policy and planning

should be guided by an awareness of the role that water plays on earth. Fresh water is a finite resource, and unlike industrial and consumer goods, water cannot be produced in response to projection to demand.

The foundations of Indian Environment Policy must, unarguably, be the Indian Consciousness. It is only on the basis of our age-old national consciousness that we will be able to truly protect and safeguard the natural environment. This consciousness is reflected in our customs, beliefs, rites and rituals and even our traditional lifestyle.
It is also evidenced by our rich history, which tells us that the Indian Civilization has always believed in the supremacy of nature.

## Linking of the Rivers

*Time and again we try to alter the natural flow of nature and again and again nature teaches us that by doing so we will pay the consequences.*

Jal Biradari believes it is more important to link community with rivers for its conservation and management rather than interlinking of rivers and to also promote community based efforts in conservation and management of natural resources such as water and forests.

Over the years the proposal of River Linking was discussed but it never materialized. Until recently in 1982 the National Water Development Agency (NWDA) was set to a high power task force under former Union Minister to "revive" a similar project.

The NWDA plan has divided the project into two broad components The Himalayan component with 14 river links estimated at 375,000 crores and the peninsular component with 16 river links estimated at 185,000 cores. This colossal scheme of linking 30 rivers all over India to enable inter-river basin transfers has been proposed by the Gov. as

a panacea for tacking problems of drought, flood and agriculture and industrial development in the country

Jal Biradari feels that before linking rivers one must rejuvenate rivers. So we are pleading to all National and State Gov to look into the problems of these rivers and see on a National, Local gov. to look into the problems of these rivers how can we save those rivers. Therefore linking of the rivers is secondary.

*It is impossible to overstate the immense significance of the proposal to interlink the rivers of this country. It will have tremendous impact in many spheres of our nation's future. We will be changing the lives of people not merely in our generation but perhaps for centuries to come. The project will forever alter the physical features of our land; its impact on our ecology and ecosystems will be profound and can never be fully predicted. The project cannot be undertaken without understanding its implications or without the informed consent of the people it affects.*

Jal Biradari is putting all its serious efforts for generating people's awareness at the national, state, agro-climatic zones, river basins and regional levels. This is a simple, self energetic, strong and active water movement due to the fact that is directly connected to life as Water is life and without it no one can survive. It has a direct effect on our body and soul. The present crisis on water is a crisis on our lives. To be safe from this crisis we have to create awareness for the water conservation through constructing water harvesting structures, and remove the obstacles coming from the Government through Satyagarh in form of the water movement namely Jal Biradari.

Jal Biradari cannot emphasize enough that everything is connected and that one must not only conserve the Water but also the Forests. Trees are like the lungs of the earth just as our rivers are like the veins,

and this natural system provides us with life. Our ancestors knew of this natural rhythm, they knew that if you take from the earth you must give it back in order to keep the balance.

Jal Biradari does not exclude anyone in the thinking process. On the contrary it hopes that Government, decision makers and stakeholders could come to their sense and approach the matter of whether river linking, pollution, depletion, conflicts over water where its heart and intention working side by side with nature. So that we can again re-establish the harmony with nature that once existed in India.

Tradition means, any good activity which links the past, present and future of our society, and traditional rainwater harvesting has stood the test of time.

Today's modern water management doesn't fulfill the thirst of society and is unable to save us from drought and floods.

Once upon a time this brotherhood of traditional water conservation was very strong.

**We can only solve the water problem to the proportion in which we revive this tradition.**

Printed at Kumar & Company, Jaipur

आयोजक

**तरुण भारत संघ**

भीकमपुरा, किशोरी, अलवर (राज.)